

प्रदेश में हरियाली तीज के दिन एक करोड़ से अधिक वृक्षारोपण

75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, "पर्यावरण संरक्षण में भागीदार बन हरियाली राजस्थान का निर्माण करें"

जयपुर, 7 अगस्त (का.सं.)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। हम ईश्वर का वास मानकर वृक्षों, नदियों और पहाड़ों को पूजते हैं। राज्य सरकार द्वारा भी इसी सोच के साथ आज हरियाली तीज के अवसर पर एक ही दिन में प्रदेशभर में 1 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए जाएंगे। इन पौधों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उपस्थित जनसमूह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान वह धरा है, जहाँ माँ अमृता देवी सहित, 363 लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था।

शर्मा बुधवार को हरियाली तीज के अवसर पर दूध के गाडोता में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में उपस्थित जनसमूह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्थान वह धरा है, जहाँ माँ अमृता देवी सहित, 363 लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने जीवन का बलिदान किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पर्यावरण दिवस पर "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान शुरू किया, जो अब जनअभियान बन गया है। उन्होंने आमजन से "एक पेड़ माँ के नाम" लगाने का संकल्प लेने की अपील की। शर्मा ने कहा कि मोदी की पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा से राज्य सरकार ने इस वर्ष "मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान" प्रारम्भ कर 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इस अभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में

मुख्यमंत्री ने कहा, आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ वृक्ष लगाए जाएंगे।

वन महोत्सव में मुख्यमंत्री ने अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार वितरित किए।

50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे तथा पौधों को पेड़ बनाने के लिए पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल भी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि, आमजन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर प्रत्येक जिले में "मातृ वन" की स्थापना की जायेगी, जिनमें विभिन्न प्रजातियों, जैसे बड़, पीपल, गुलर, पिलखन, नेती पीपल, माखन कटोरी इत्यादि पौधे लगाये जाएंगे। वृक्ष प्रेमियों को "राज जिओ ट्री एप" के माध्यम से 51 लाख प्रशस्ति पत्र वितरित किये जाएंगे। पौधों की देखरेख के लिए 2 हजार 'वन मित्र' लगाए जा रहे हैं, जिसके तहत इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी को संरक्षक के रूप में जिम्मेदारी दी जायेगी।

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी को जागरूकता से काम करना होगा, जिससे आने वाली पीढ़ी को हम एक स्वच्छ एवं सुरक्षित धरोहर दे सकें।



प्रदेश में हरियाली तीज के मौके पर बुधवार को एक करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए गए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी दूध के गाडोता में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में 50 करोड़ पेड़ लगाये जायेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने वृक्षारोपण की अनुपम पहल के तहत अधिक से अधिक पेड़ लगाने का आह्वान किया। वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य में पर्यावरण संरक्षण के लिए नित नए नवाचार किए जा रहे हैं, आने वाले दिनों में देश में सबसे ज्यादा पौधे राजस्थान में लगाए जाएंगे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज अभय कुमार ने बताया कि मिशन हरियाली राजस्थान की थीम के तहत हरियाली तीज के अवसर पर दो करोड़ से अधिक पौधे राजस्थान में लगाए गये हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधिपूर्वक मंत्रोच्चार के साथ पीपल का पौधा लगाकर हरियाली राजस्थान अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने पेड़ को मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जियो टैग भी किया तथा ड्रोन के माध्यम से वीजरोपण करने की तकनीक का निरीक्षण किया एवं स्वयं ड्रोन उड़ाकर परिसर में वीजरोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने "बर्ड्स ऑफ जयपुर", "खेजड़ी" और "मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महा अभियान-2024" पुस्तकों का विमोचन भी किया।

मुख्यमंत्री ने महोत्सव में अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार के तहत वन विकास एवं वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार दिए। कार्यक्रम में देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, जिला प्रमुख रमा देवी, जयपुर ग्रेटर महापौर सोम्या गुर्जर, मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू, अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार सहित अनेक वरिष्ठ जन उपस्थित थे।

एन.सी.ई.आर.टी...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

"संविधान पर हमला तो कांग्रेस सरकार ने जून 1975 में किया था। केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने 90 से अधिक निर्वाचित राज्य सरकारें गिरायी थीं।" केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान भी इस बहस में शामिल हो गये तथा उन्होंने खड़गे के आरोपों को "निराधार" बताया।

एक दशक में बांग्लादेश...

(प्रथम पृष्ठ का शेष) एक निम्नतम गरीब देश से क्षेत्र की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में तब्दील हो गया और इतना ही नहीं, उसने आर्थिक प्रगति के मामले में अपने पड़ोसी भारत को भी पीछे छोड़ दिया।

देश की प्रति व्यक्ति आय एक दशक में तीन गुना बढ़ गई और विश्व बैंक का अनुमान है कि गत 20 वर्ष में बांग्लादेश के 25 मिलियन लोग गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठ गए। हसीना की सरकार ने गंगा नदी के आर-पार 2.9 अरब डॉलर के पद्म ब्रिज प्रोजेक्ट जैसे महत्वाकांक्षी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हाथ में लिए। इनके लिए घरेलू फंड, लोन और विकास सहायता का इस्तेमाल किया गया।

लेकिन इन आर्थिक लाभों की महंगी कीमत चुकानी पड़ी। वर्ष 2014, 2018 और 2024 के संसदीय चुनावों पर विपक्षी पार्टियों के बहिष्कार, हिंसा और कम मतदान का साया रहा। जनता को नियंत्रित रखने के लिए हसीना की सरकार लगातार निरंकुश होती चली गई, जिससे लोगों में भय व्याप्त हो गया। वर्ष 2018 में लागू किया गया "डिजिटल सिन्क्रोटी एक्ट" सरकार और सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अपने अलोचकों को, खासतौर पर ऑनलाइन विरोध को, चुप कराने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

का गला घोटने का एक सक्षम हथियार बन गया।

सत्ता के केन्द्र पर जैसे-जैसे हसीना की पकड़ मजबूत होती गई, वैसे-वैसे प्रेस की स्वतंत्रता को परेशान होना पड़ा और नागरिक अधिकार सुनियोजित ढंग से दबा दिए गए। अर्थव्यवस्था में जहाँ प्रगति हुई, वहीं अमीर-गरीब के बीच विभाजन की खाई भी बढ़ती गई। बैंक चोटलों की संख्या के साथ-साथ, बैंक लोन की किस्में न चुकाने वाले लोगों की भी तादाद बढ़ गई। सी.एल.सी. पावर, वेस्टर्न मरीन शिपयार्ड और रिमेक्स फुटवियर जैसी कम्पनियों डिफॉल्टर्स की सूची में शीर्ष पर थीं। डूबत ऋणों की मात्रा 965 से लेकर 1,649 करोड़ बांग्लादेशी मुद्रा तक पहुंच गई। समग्र आर्थिक प्रगति के बावजूद निरंकुश भ्रष्टाचार और बढ़ती आर्थिक असमानता के कारण जनता का असंतोष बढ़ गया।

बांग्लादेश की कुल आबादी 170 मिलियन है और यहाँ के करीब 18 मिलियन युवा बेरोजगार हैं। बांग्लादेश दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह देश करीब 40 बिलियन डॉलर मूल्य के कपड़ों का निर्यात ग्लोबल मार्केट में करता है। यहाँ के रिटेल सैक्टर में महिलाओं सहित 4 मिलियन लोगों को

रोजगार मिला है। लेकिन यह आर्थिक विकास देश के युवाओं को रोजगार देने में विफल रहा।

हसीना की आर्थिक उपलब्धियाँ जहाँ प्रशंसनीय हैं, वहीं उनका कठोर शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उपेक्षा उनके पतन का कारण बने। बांग्लादेश जैसे-जैसे आगे बढ़ रहा है, वह अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति विश्वास बहाली एवं हाल ही वर्षों में उभरी असमानता के समाधान की चुनौतियों से भी जूझ रहा है।

बांग्लादेश का घटनाक्रम आर्थिक प्रगति और लोकतांत्रिक सुशासन के संतुलन के साथ ही पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के महत्व को रेखांकित करता है क्योंकि इनके बिना बहुतां की कीमत पर कुछ लोग लाभान्वित होते हैं। हसीना अपने पूर्ववर्तियों, जैसे कि अलोकपित्र रहे सेना प्रमुख एच.एम. इरशाद के विपरीत देश छोड़कर चली गई। इरशाद जेल में रहे किन्तु देश छोड़कर नहीं भागे। हसीना अब पाकिस्तान के उन शासकों की जमात में शामिल हो गई हैं, जिन्होंने अपने पक्ष में लड़ने के बजाए सुरक्षित देशों में शरण लेना बेहतर समझा। क्या हसीना का कथानक बांग्लादेश के किसी अन्य पड़ोसी देश से मिलता-जुलता प्रतीत होता है?

भारत के लिए अजनबी नहीं हैं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि रिपोर्ट बताती हैं, उनके पास 15 सलाहकारों की एक पूरी टीम होगी। यह टीम सम्भवतः सैन्य प्रमुख के प्रति जवाबदेह होगी, जिनके मार्गदर्शन के अन्तर्गत, अन्तरिम सरकार बनाई जा रही है। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वास्तविक सत्ता तो सेना के पास होगी तथा सलाहकारों की टीम सैन्य-शासन के निर्धारित ढाँचे के अन्दर काम करेगी। अन्तरिम सरकार शीघ्र ही होने वाले अगले चुनावों का संचालन तथा निगरानी करेगी।

अन्तरिम सरकार की व्यवस्था युनुस के अधीन रखे जाने का निर्णय, सैन्य प्रमुख, बांग्लादेश के राष्ट्रपति तथा छात्रनेताओं की एक संयुक्त मीटिंग में लिया गया था। अन्तरिम सरकार के प्रमुख के रूप में मोहम्मद युनुस के नाम का प्रस्ताव छात्र नेताओं ने रखा था। इसके बदले में, मोहम्मद युनुस ने कहा है कि आन्दोलनकारी छात्रों ने निरंकुश सरकार को अपदस्थ करने के

लिये भारी कुर्बानियाँ दी हैं। अन्तरिम सरकार के प्रमुख के पद को स्वीकार करके, युनुस के आन्दोलनकारी छात्रों की इच्छाओं के प्रति केवल सम्मान प्रकट कर रहे थे। अन्तरिम सरकार के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ होंगी - देश में शान्ति की बहाली, तथा हसीना के देश छोड़ कर चले जाने के बाद हो रही

भयंकर हिंसा, जिसमें पिछले दो दिनों में कम से कम 500 लोग मारे गये हैं। देश में तालिबानी हिंसा और अव्यवस्था की तस्वीरें दिखाई दीं। राजधानी में लोग मार दिये गये और उसके बाद, उनकी लाशें फ्लाई-ओवरों तथा पुलों से उल्टी लटक दी गई थीं।

'कोशिश मैडल जीतने ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रदर्शन करके अपना कैरियर व आत्मसम्मान पुनः स्थापित करने के लिए एक जंग लड़ी। फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के बाद, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तुरंत हरियाणा में उनके परिवार से मिलने गए। इस साल हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस इसे एक बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की पूरी तैयारी में है, जबकि हरियाणा में भाजपा की

स्थिति पहले ही कमजोर है। एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने कहा कि इससे चुनाव में भाजपा को और नुकसान होगा। सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से फोगाट के संबंध में लिए गए निर्णय का रिज्यू करने की मांग की है। तथापि, प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि क्या यह प्रयास किया गया कि फोगाट को मैडल मिले, या वह सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ कि फोगाट को मैडल न मिले?

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार का अनुपम उपहार

गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी की अब अधिकृत निजी केन्द्रों पर भी निःशुल्क सेवा

श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

MAA वाउचर योजना

आज से सम्पूर्ण राज्य में

शभांभु

मुख्य अतिथि
श्री भजनलाल शर्मा
माननीय मुख्यमंत्री

दिनांक : 08 अगस्त, 2024
समय: दोपहर 2.00 बजे
स्थान : मुख्यमंत्री निवास

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर